शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 49 अंक-28 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 1-8 जुलाई 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या यह छापेमारी राजनेताओं तक भी पहुंचेगी? ईडी के आने से उठी चर्चा

➤ होटल और स्टोन क्रेशर की जांच की आंच दूर तक जाने की संभावना
➤ क्या विलेज कामन लैण्ड की खरीद-बेच का मुद्दा भी उठेगा?

शिमला/शैल। हमीरपुर में केंद्रीय एजैन्सियों का एक सप्ताह में ही दूसरी बार छापेमारी करना निश्चित रूप से प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि पहली बार केवल आयकर विभाग ने हमीरपुर और नादौन में नौ जगहों पर छापेमारी की थी। लेकिन दूसरी बार नादौन में आयकर विभाग के साथ ईडी और सीआरपीएफ की टीमें भी साथ रही है। पहली बार करीब 38 घंटे आयकर विभाग की कारवाई चली है। दूसरी बार नादौन में करीब 56 घंटे तक यह कारवाई चली है। इन एजैन्सियों ने न पहली बार और न ही दूसरी बार यह जानकारियां मीडिया से सांझा की है कि उन्हें यह छापों में क्या मिला है। नादौन के जिन तीन कारोबारीयों के यहां छापेमारी हुई है उनमें एक स्टोन क्रेशर का मालिक है और एक होटल कारोबारी है। जिस स्टोन क्रेशर पर छापेमारी हुई है वह शायद पहले नादौन के ही जरोट गांव में स्थित था और अवैधता के कुछ आरोपों के चलते एनजीटी ने उसे वहां से हटाये जाने के आदेश किये थे। एनजीटी के आदेशों के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील भी हुई थी जिसे जस्टिस सूर्यकान्त ने गंभीर टिप्पणियों के साथ अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद यह स्टोन क्रेशर अब ज्वालामुखी के अधवाणी में स्थापित है। अधवाणी में भी इसकी स्वीकृति पर सवाल उठ चुके हैं। इस पृष्ठभूमि में संभव है कि इस क्रेशर को लेकर बहुत कुछ ऐसा सामने आ जाये। जिसमें कई चेहरे बेनकाब हो जाये। क्योंकि इस क्रेशर को लेकर कुछ वीडियो वायरल होते रहे हैं जिन पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है।

जिस होटल पर छापेमारी हुई है उसकी जमीन एक समय शायद राजा नादौन से खरीदी गयी है। राजा नादौन द्वारा बेची गयी जमीन अपने में एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। यदि यह मुद्दा उठता है तो इसकी आंच बहुत लोगों को झुलस देगी। इसकी आंच प्रशासन पर भी पड़ेगी। क्योंकि राजा नादौन को 1897 में अंग्रेज शासन काल के दौरान जागीर मिली थी। यह जागीर रियासत के 329 गांवों में फैली थी। लेकिन इस जागीर पर राजा के साथ स्थानीय लोगों के बर्तनदारी के हक भी यथा स्थिति बहाल रखे गये थे। 1974 में जब प्रदेश में लैण्ड सीलिंग एक्ट आया और इसमें अधिकतम भू-सीमा 300 कनाल कर दी गयी। जिसका अर्थ था कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 300 कनाल से अधिक का मालिक नहीं हो सकता। लैण्ड सीलिंग के दायरे में प्रदेश के सभी राजघराने भी आ गये। इस तरह राजा नादौन की एक लाख कनाल से अधिक जमीन सर प्लस घोषित हो गयी। 1974 में कलैक्टर हमीरपुर सब डिवीजन ने यह आदेश पारित किये थे। इसके बाद इस मामले में आयी सारी अपीलों आदि के निपटारे के बाद वित्तायुक्त आर.के.आनन्द ने 31-7-84 से पारित अपने फैसले में 1974 में कलैक्टर हमीरपुर सब डिवीजन द्वारा पारित फैसले को बहाल रखा और राजा नादौन की एक लाख कनाल से अधिक जमीन विलेज कामन लैण्ड बन गयी। राजस्व रिकॉर्ड में इस पर "ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान" का अन्दराज दर्ज है।

लेकिन राजा नादौन इन जमीनों को अदालत के इन फैसलों के बाद भी बेचता रहा। प्रशासन इस पर मौन रहा। राजस्व अधिकारियों ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। अब जिस होटल की जांच ईडी और आयकर ने की है उसकी जमीन ऐसी ही विलेज कामन लैण्ड होने की संभावना है।

शेष पृष्ठ 8 पर......................

उपचुनाव में सरकार की सफलता संदिग्ध

⇨ होशियार सिंह की गाड़ी का पीछा किया जाना नुकसान देह
⇨ वायरल वीडियो ने बदले समीकरण

शिमला/शैल। उपचुनावों का परिणाम क्या रहता है इसका अंतिम पता तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो कुछ चुनाव प्रचार के दौरान घटा है उसका यदि निष्पक्ष आकलन

किया जाये तो बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाती है इस उप चुनाव में कांग्रेस ने देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी को चुनाव में उतारा। कमलेश ठाकुर की उम्मीदवारी कांग्रेस हाईकमान के सर्वे के आधार पर तय हुई कही गयी। कमलेश की सक्रिय राजनीति में भागीदारी इस उप चुनाव से शुरू हुई है। इसलिये सर्वे के आधार पर कमलेश का चयन सरकार की कारगुजारी के आकलन पर हुआ होगा ऐसा माना जा रहा है। कमलेश मुख्यमंत्री की पत्नी है इसलिये देहरा में यह उपचुनाव सरकार बनाम विपक्ष बन गया है। प्रदेश में सरकार की कारगुजारी कितनी प्रभावशाली रही है इसका पता लोकसभा चुनावों में चल गया है। देहरा में कांग्रेस कितनी सशक्त है इसका पता इससे भी चल जाता है कि यहां पर चुनाव प्रचार के लिये हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शिमला से ले जाने पड़े हैं। यही नहीं जब यह तथ्य सामने आया कि भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की गाड़ी के पीछे एक टैक्सी नंबर की गाड़ी तीन दिन से उसके पीछे लगी हुई थी। जब इस गाड़ी को रोक कर होशियार सिंह ने गाड़ी में बैठे लोगों से पूछा तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। प्रशासन ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। होशियार सिंह ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों और प्राइवेट गाड़ी में सरकार ने उसके पीछे पुलिस उसकी जासूसी करने को लगा रखी थी। होशियार सिंह ने इसे अपने लिये खतरा बताया है। इसी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव की स्थितियां एकदम बदल गयी हैं। क्योंकि न तो कांग्रेस ने और न ही सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जारी की है।

इसी तरह इस उपचुनाव के दौरान हमीरपुर और नादौन में आयकर और ईडी की छापेमारी ने राजनीतिक समीकरणों को एकदम पलट कर रख दिया है। प्रदेश के शीर्ष प्रशासन को लेकर यह चर्चाएं चल पड़ी है कि बहुत सारे

शेष पृष्ठ 8 पर......................

राज्यपाल ने जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल व जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल ने जिला सोलन के वाकनाघाट स्थित जेपी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों से निरंतर बदलाव के दौर में कौशल और ज्ञान के समावेश से देश के विकास में अपना अहम योगदान सुनिश्चित करने का आहवान किया। राज्यपाल ने वर्ष 2015-2020 के दौरान एम.टेक, एम. फार्मा, बी.टेक और बी.फार्मा पाठ्यक्रमों में उच्च सीजीपीए हासिल करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया।

शिव प्रताप शुक्ल ने विद्यार्थियों से कहा कि उनकी सफलता में उनके परिजनों, मार्गदर्शकों और शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह एक संस्कार है जहां एक अध्याय के समाप्त होने के साथ ही दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है और इस अध्याय में असीमित संभावनाएं हैं। यह अध्याय जीवन की एक नई दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि भारत में इस समय कृत्रिम मेधा, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में निरंतर नवाचार हो रहे हैं। यह तकनीक का एक नया युग है। इस प्रगति से औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं और रोजगार सृजन में भी काफी मदद मिल रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि तकनीक के इस युग का भरपूर लाभ उठाएं और देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने में अपना अहम योगदान दें। राज्यपाल ने कहा कि तकनीक और इंजीनियरिंग राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण अंग हैं। इंजीनियर और वैज्ञानिक आधुनिक समाज, नवाचार और नए समाधानों के निर्माता हैं जो समुदाय की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपने ज्ञान और कौशल से सकारात्मक बदलाव लायें और सतत विकास को प्रोत्साहित करते हुए एक समावेशी समाज का निर्माण करें। शिव प्रताप शुक्ल ने विश्वविद्यालय की सराहना करते हुये कहा कि इस संस्थान ने आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम बनाया है और उत्कृष्टता का यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि संस्थान की परंपरा को इसके गर्व, सिद्धांतों और मूल्यों के साथ आगे बढ़ाएं और संस्थान से मिले ज्ञान के लिए हमेशा इसके आभारी रहें क्योंकि यहीं से विद्यार्थी के जिम्मेदार नागरिक बनने और बेहतर जीवन जीने की शुरूआत होती है।

इससे पूर्व, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति मनोज गौड़ ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला के विचार ''शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं'' को अंगीकार कर हम विश्व में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भौतिक सुख-सुविधा और पेशेवर जीवन में सफलता अर्जित करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को अन्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और इतिहास पर अंकित होने वाले कार्यों से अपनी सफलता को आंकना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने, भगवत गीता को आत्मसात करने और जीवन के अनुभव ग्रहण करने का सुझाव दिया।

जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति आर.के. शर्मा ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। विश्वविद्यालय को 26 अप्रैल, 2024 को पांच वर्षों के लिए नैक से ए-प्लस ग्रेड, क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी-2024, टाईम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रतिष्ठित स्थान और विभिन्न पैटेंट्स, प्रकाशनों, कार्यक्रमों तथा अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान उपलब्धियां हासिल हैं।

इसके उपरान्त, राज्यपाल की गरिमापूर्ण उपस्थिति में कुलपति डॉ. आर.के. शर्मा ने 3,125 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कीं। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार आनन्द बोध के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने द टाईम्स ऑफ

इंडिया के वरिष्ठ सहायक सम्पादक आनन्द बोध के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला में हृदय गति रुकने के कारण निधन हुआ।

राज्यपाल ने कहा कि आनन्द बोध ने पत्रकारिता के क्षेत्र में समर्पण से कार्य किया तथा समाज से जुड़े अहम् मुद्दों को समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि श्री बोध राज्य के विभिन्न समाजहित से जुड़े मुद्दों एवं राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में गहन समझ रखते थे। पत्रकारिता जगत में उन्हें तथ्य आधारित पत्रकारिता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि आनन्द बोध का निधन समाज के लिए विशेष तौर पर मीडिया जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने आनन्द बोध के आकस्मिक निधन को मीडिया जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि श्री बोध हिमाचल से संबंध रखते थे तथा उन्होंने राज्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में लम्बी सेवाएं दी हैं, इस कारण उन्हें हिमाचल से जुड़े मुद्दों की गहन समझ थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री बोध ने हिमाचल के हितों से जुड़े अनेकों मुद्दों को समाचार पत्र के माध्यम से लोगों के बीच रखा, जिससे उनका हिमाचल के विकास के प्रति समर्पण दिखता है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कुल्लू के लिए भेजी राहत सामग्री

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज भवन से कुल्लू जिला के लिए राहत सामग्री के साथ वाहनों को

हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राहत सामग्री में स्वच्छता किट, तिरपाल, किचन सेट और कंबल इत्यादि शामिल हैं।

इस अवसर पर शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि बीते वर्ष बारिश से हुए भारी नुकसान के कारण इस वर्ष हर स्तर पर पूरी तैयारी, सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा भी उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी संभावित स्थिति में लोगों को तुरंत राहत उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य रेड क्रॉस ने विभिन्न जिलों में राहत के तौर पर 3438 स्वच्छता किट, 1189 कंबल, 2057 तिरपाल, 2085 किचन सेट और 36 फैमिली टेंट उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राहत सामग्री सर्वप्रथम कुल्लू भेजी गई है और इसी तरह अन्य जिलों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

शिव प्रताप शुक्ल ने अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग बरसात के इस मौसम के दौरान सतर्क रहें। उन्होंने पर्यटकों से भी नदी-नालों के किनारे न जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटक स्थानीय प्रशासन को अपनी यात्रा की जानकारी जरूर दें। राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी इस मौके पर उपस्थित थे।

आपदा के दौरान बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गैर सरकारी संस्था बाल रक्षा भारत के साथ गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रदेश सरकार की ओर से निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा तथा निदेशक प्रोग्राम सपोर्ट, बाल रक्षा भारत शांतनु चक्रवर्ती ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहभागिता से आपदा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में बाल केंद्रित आपदा प्रबंधन रणनीति बनाने तथा बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण करने में मदद मिलेगी। यह समझौता 6 जुलाई 2029 तक प्रभावी होगा।

आपदा के दौरान बच्चों की मनोस्थिति के साथ-साथ उनके विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके दृष्टिगत बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुआयामी योजना व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रयास करना नितांत आवश्यक है।

इस समझौते के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा एवं उनके संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की भी इसमें अहम भूमिका होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों और आशा कार्यकर्ताओं के समन्वय से ऐसा तंत्र विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि आपदा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बच्चों के लिए जीरो डे लॉस और जीरो डेथ अवधारणा सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण विशेषज्ञ डॉ. कृष्ण चंद और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ नवीन शुक्ला उपस्थित थे।

आचार संहिता के दौरान 3.31 करोड़ की अवैध शराब, नकदी, आभूषण जब्त

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने वाले उप-चुनावों के लिए 10 जून, 2024 से लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस, आबकारी और अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा 3. 31 करोड़ रुपये की अवैध शराब, नकदी, आभूषण जब्त किए गए हैं। यह जानकारी निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने दी

उन्होंने बताया कि राज्य कर एवं आबकारी तथा पुलिस विभाग ने 14.12 लाख रुपये मूल्य की 10358 लीटर अवैध शराब जब्त की। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने 2.13 करोड़ रुपये मूल्य के 3.13 किलोग्राम आभूषण व कीमती धातुओं को जब्त किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस व आयकर विभाग ने अब तक 93. 66 लाख रुपये की नकदी जब्त की है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 2.65 लाख रुपये मूल्य की 1.06 किलोग्राम चरस, 3.82 लाख रुपये मूल्य की 19 ग्राम हेरोइन, 91,800 रुपये मूल्य की 4. 59 ग्राम स्मैक और 19,890 रुपये मूल्य की 1.32 किलोग्राम चूरा पोस्त जब्त की है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान उद्योग विभाग द्वारा खनन अधिनियम के तहत दर्ज 74 मामलों में 2.67 लाख के जुर्माने लगाए गए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए जारी की गई पुरस्कार राशि

शिमला/शैल। युवा सेवा एवं खेल विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल संस्कृति और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 65 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 22 जनवरी, 2022 तक विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के 102 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए यह राशि जारी की गई है। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी द्वारा इस राशि का वितरण किया जाएगा।

उन्होंने पात्र खिलाड़ियों से आग्रह किया कि आवेदनकर्ता खिलाड़ी पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए अपने सम्बन्धित जिला के खेल अधिकारी से सम्पर्क करें।

किसी पौंग बांध विस्थापित को भूमिहीन नहीं रहने देंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी पौंग बांध विस्थापित परिवार को भूमिहीन नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस मामले को देखेंगे और क़ानून भी बदलना पड़ा तो क़ानून बदल देंगे, लेकिन विस्थापितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1972 से 20,722 प्रभावित परिवार न्याय की आस में दर-दर भटक रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ लेकिन अब कांग्रेस सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाएगी।

उन्होंने कहा कि देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह केवल छः साल तक अपने विकास में लगे रहे और देहरा की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। कभी कल्पना भी नहीं की कि देहरा इतना पिछड़ा होगा और लोगों को बिजली, पानी और सड़क की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देहरा अब हमारा हो चुका है और यहां की समस्याओं का समाधान करना मेरा दायित्व है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता होशियार सिंह अपना इस्तीफ़ा मंज़ूर कराने को धरना देने की बजाये देहरा की समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन करते। लेकिन पूर्व विधायक एक चुनी हुई सरकार को गिराने की षडयंत्र में शामिल हो गये और भाजपा की राजनीतिक मंडी में बिक गये।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब देहरा की जनता से पांच वर्ष के लिए होशियार सिंह को निर्दलीय विधायक के रूप में चुना था, तो उन्हें डेढ़ साल में ही त्यागपत्र देने की क्या आवश्यकता थी। अब विधायकी छोड़कर साढ़े तीन वर्ष के लिए दोबारा विधायक बनने के लिए वोट मांग रहे हैं। विधायक पद से इस्तीफ़ा देने से पहले उन्होंने

देहरा के मतदाताओं से एक बार पूछा तक नहीं कि वह इस्तीफ़ा दें या न दें। उन्होंने कहा कि होशियार सिंह विधायक बनने के लिए वोट नहीं मांग रहे, बल्कि अपने अधूरे रिजॉर्ट का काम पूरा कराने के लिए वोट मांग रहे हैं। छः महीने पहले मैंने देहरा आकर क्षेत्र के लिए घोषणाएँ की और होशियार कह रहे हैं कि मेरे काम कांग्रेस सरकार में नहीं हो रहे। सत्य यह है कि विधायक रहते हुए भी होशियार सिंह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कभी नहीं आये। विधायक को प्रति वर्ष क्षेत्र के विकास के लिए दो करोड़ मिलते हैं, होशियार सिंह बताये छः साल के 12 करोड़ रुपए कहां गए। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अब जनता के सामने बेनक़ाब हो चुके हैं और बिके हुए विधायक को सबक़ सिखाने के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी है। यह देहरा का भाग्य ही होगा कि उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को कांग्रेस आलाकमान ने एक सर्वे के आधार पर पार्टी का प्रत्याशी बनाकार चुनाव मैदान में उतारा है और अब क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के पहले ही दिन से लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाज़े बंद कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में 20 प्रतिशत का सुधार लाकर 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है, जिससे जन कल्याण की योजनाएँ बनाकर लोगों में बाँटा जा रहा है। इस अवसर पर कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा, जिलाध्यक्ष कर्ण पठानिया, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी, मनमोहन कटोच सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

हमीरपुर, देहरा व नालागढ़ के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह में कहा है कि प्रदेश की तीनों विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल कर रही है। हमीरपुर, देहरा व नालागढ़ के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और लोग प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मजबूत करने के लिये एकजुट है। तीन उप चुनावों के बाद प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 41 होने जा रही है।

प्रतिभा सिंह ने जारी एक बयान में कहा है कि भाजपा का कोई भी राजनैतिक दांव अब प्रदेश में चलने वाला नही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उप चुनावों के लिये भाजपा पूरी तरह जिम्मेदार है और इससे वह कभी भी दोषमुक्त नही होगी।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि तीनों पूर्व निर्दलीय विधायकों ने अपने मतदाताओं के उस भरोसे को तोड़ा है जिसके लिए उन्होंने उन्हें चुना था। इसलिए उन्हें अब क्षेत्र के लोग कभी माफ नही करेंगे। उन्होंने कहा है कि इन तीनों पूर्व विधायकों को लोगों से अपने इस कृत्य के लिये माफी मांगनी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब चुनाव के तीन दिन शेष रह गए है ऐसे में उन्हें कांग्रेस के प्रति भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार से मतदाताओं को सचेत करते हुए पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पूरा करना है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस बहाल कर व महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि जारी कर अपनी गारंटी को पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जनहित के प्रति पूरी तरह समर्पित है।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा झूठी बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। लोग भाजपा की नीति व नियत से भली भांति परिचित है।सत्ता हतियाने के लिये प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को जिस प्रकार से अस्थिर करने की कोशिश की गई थी वह प्रदेश के लोकतंत्र व जनमत का अपमान था जिसे कभी सहन नही किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह मजबूत है जो अपना कार्यकाल सफलता पूर्वक पूरा करेगी।

10 जुलाई को प्रातः 7 बजे से सायं 6.30 बजे तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने देहरा, हमीरपुर व नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों के दृष्टिगत 10 जुलाई, 2024 को प्रातः 7 से सायं 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है।

उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री, ओपिनियन पोल के परिणाम अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण के प्रसारण पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।

धूमल को कमजोर करने के लिए जयराम ने हमीरपुर में नहीं किया विकास:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल के हारने का हमीरपुर जिला को बड़ा नुकसान हुआ। बीते 5 साल जिला में विकास कार्य नहीं हुए। जयराम ने धूमल को

कमजोर करने के लिए हमीरपुर में विकास रोक दिया। हमीरपुर से कोई मंत्री नहीं बनाया। धूमल 2017 में घोषित मुख्यमंत्री थे, उन्हें साजिश के तहत हराया गया। इसमें भाजपा के साथ वे लोग शामिल थे, जिन्होंने वर्तमान सरकार को गिराने की साजिश रची। किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमीरपुर जैसे छोटे जिला को दोबारा मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन, कांग्रेस ने पहली बार निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाया। मेरे ही जिला के तीन विधायक सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल हुए। दूसरे जिलों के विधायक व लोग अपने जिले का मुख्यमंत्री चाहते हैं और हमीरपुर जिला के तीन विधायक मुख्यमंत्री को हटाने में ही लग गये। ये वही लोग हैं जिन्होंने धूमल को हराने की भी साजिश रची। मुख्यमंत्री ने ये बातें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. पुष्पिंदर वर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि जब सरकार गिराने की कोशिश हुई तो शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू, ऊना के दो, चंबा इत्यादि जिलों के 34 विधायक चटान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन हमीरपुर जिला के तीन विधायकों ने गद्दारी की। उनमें शामिल आजाद विधायक आशीष शर्मा पैसे के अहंकार में हैं। उन्होंने अहंकार में ही 14 महीने में इस्तीफा दिया और सोचा कि पैसे के दम पर वोट खरीदकर साढ़े तीन साल के लिए दोबारा विधायक बन जाएंगे। मेरा हमीरपुर की जनता से अनुरोध है कि धनबल की राजनीति करने वालों को कड़ा सबक सिखाएं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि पूर्व निर्दलीय विधायक ने जनता की खनिज संपदा को लूटकर संपत्ति बनाई है। वह निर्दलीय विधायक थे, अगर कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही थी तो भाजपा के साथ विपक्ष में बैठ जाते, इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। अब भी वह विधायक बनने का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पहले काम नहीं हो रहे थे तो अब किससे उम्मीद है कि काम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं, साढ़े तीन साल हमारी सरकार है, अगर गलती से विधायक बन गये तो काम फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि काम तो मैंने ही करने हैं। इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. पुष्पिंदर वर्मा को वोट दें। पुष्पिंदर ईमानदार व्यक्ति हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं। इन्हें एक मौका दीजिये, यह जो भी काम बताएंगे, मैं सारे काम करूँगा। लोगों की पानी, बस व सड़क इत्यादि की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार में हमीरपुर अधीनस्थ चयन बोर्ड में पेपर बिकते रहे और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहते चैन की नींद सोये रहे। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद चयन बोर्ड को भंग किया और पेपर बेचने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। जयराम ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उनके समय की सारी भर्तियां कोर्ट में लटकी रहीं, हमारी सरकार ने सही तरीके से कोर्ट में पैरवी कर रिजल्ट निकालने व नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की है। हमने 14 महीने में 22 हजार सरकारी भर्तियां निकाली हैं, जयराम सरकार ने 5 साल में मात्र 20000 हजार सरकारी नौकरियां दी। हमीरपुर में 15 साल से अधर में अटके बस स्टैंड का काम शुरू करवाया। परिवहन अपीलेट प्राधिकरण, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सौर ऊर्जा का मुख्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय दिया। गांधी चौक की सूरत बदली, पूरे शहर की बिजली की तारों को हटाकर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा करोड़ों रुपये के बिजली, पानी व सड़कों के काम जारी हैं। जनता जिला के मुख्यमंत्री व विकास के लिए पुष्पिंदर को वोट दे। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक सुरेश कुमार, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया, पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार, जिलाध्यक्ष सुमन भारती, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर, जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार, पंचायत प्रधान, बीडीसी व जिला परिषद सदस्य इत्यादि मौजूद रहे।

हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की बैंकर्स एसोसिएशन के साथ बैठक

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आज यहां राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ यूको बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने अपने-अपने एटीएम में एचआईवी और टीबी जागरुकता पर एड्स नियंत्रण समिति द्वारा बनाए गए पोस्टर लगाने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एचआईवी और टीबी के बारे में जागरुक किया जा सके।

राज्य एड्स नियंत्रण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य बैंकर्स एसोसिएशन की कार्यप्रभारी कुसुम, इंडी गठबंधन से मोना बलानी और प्रदेश के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान प्रदेश में एचआईवी के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए राज्य में बैंकों की भूमिका पर चर्चा की गई। वहीं, एचआईवी से संक्रमित लोगों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण देकर एक कार्यप्रणाली सुनिश्चित किए जाने के विषय पर भी चर्चा हुई।

बैंकर्स समिति की कार्यप्रभारी कुसुम ने सभी प्रमुख बैंकों को बैठक के दौरान मोना बलानी ने बताया कि अन्य राज्यों में बैंक कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट सीएसआर के तहत एचआईवी से संक्रमित लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से प्रदेश में एचआईवी से संक्रमित लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को एचआईवी के प्रति जागरुक करने, राज्य एड्स नियंत्रण समिति की सहायता करने और प्रदेश में एचआईवी से संक्रमित बच्चों को सीएसआर बजट के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील की ताकि ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

जितना बड़ा संघर्ष होगा,
जीत उतनी ही शानदार होगी।
...... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

आउटसोर्स के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती घातक होगी

हिमाचल सरकार छः हजार प्री प्राईमरी शिक्षक आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती करने जा रही है। इसकी अधिसूचना जारी हो गयी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को यह भर्तीयां करने का काम सौपा गया है। दो वर्ष का एन.टी.टी. डिप्लोमा धारक इन भर्तीयों के लिये पात्र होंगे। इन लोगों को दस हजार का मानदेय देना तय हुआ है। लेकिन इस मानदेय में से एजेन्सी चार्जेस जी.एस.टी. और ई.पी.एफ. की कटौती के बाद इन अध्यापकों को करीब सात हजार नकद प्रतिमाह मिलेंगे। प्रदेश के 6297 प्री प्राईमरी स्कूलों में करीब साठ हजार बच्चे पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा लागू की गयी है। यह माना गया है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास छः वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरम्भिक छः वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विकास के लिए एनसीईआरटी द्वारा आठ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारम्भिक बाल्यावस्था के शिक्षा के लिए 0-3 वर्ष और 3-8 वर्ष के लिए दो अलग-अलग सबफ्रेमवर्क विकसित किये गये हैं। नई शिक्षा नीति में यहां बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एक मूल आधार है। इस आधार पर ही अगली ईमारत खड़ी होगी। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पिछले दो वर्षों से तैयारी की जा रही है लेकिन इस तैयारी के बाद जो सामने आया है वह यह है कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से प्री प्राईमरी शिक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं जिनकी पगार एक मनरेगा मजदूर से भी कम होगी। आउटसोर्स के माध्यम से रखे जा रहे इन शिक्षकों को कभी भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पायेगा। इस समय सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 45000 कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त हैं जो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं है।

जब एक सरकार शिक्षा जैसे क्षेत्र में आउटसोर्स के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करने पर आ जाये तो उसकी भविष्य के प्रति संवेदनशीलता का पता चल जाता है। निश्चित है कि आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किये जा रहे इन प्री प्राईमरी शिक्षकों का अपना ही भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं होगा तो वह उन बच्चों के साथ कितना न्याय कर पायेंगे।

जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जायेगी। यह प्री प्राईमरी शिक्षक अवधारणा नयी शिक्षा नीति का बुनियादी आधार है और इस आधार के प्रति ही इस तरह की धारणा होना कितना हितकर होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार एक ओर अटल आदर्श विद्यालय और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने की घोषणा कर रही है। स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की योजनाएं जनता में परोस रही है। जबकि दूसरी ओर आज भी स्कूलों में शिक्षकों के सैकड़ो पद खाली चल रहे हैं। दर्जनों स्कूलों का बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम शून्य रहा है। इसके लिये अध्यापकों के खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला लिया जा रहा है। लेकिन इसका कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है कि कब तक शिक्षकों के खाली पद भर दिये जायेंगे।

इस समय प्रदेश में पांच इंजीनियरिंग कॉलेज कार्यरत है इसमें प्लस टू के बाद जेईई परीक्षा के बाद दाखिला लेते हैं। लेकिन इन सभी कॉलेजों में सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। इन संस्थानों में शिक्षकों के खाली पद कब भरे जायेंगे इस ओर भी सरकार की कोई गंभीरता सामने नहीं आयी है। इस तरह शिक्षा के हर स्तर पर सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। इससे यही स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र के प्रति सरकार की गंभीरता केवल भाषणों तक ही सीमित है। व्यवहार में शिक्षा सरकार के प्राइमरी एजेण्डा के बाहर है। शिक्षा जैसे क्षेत्र में आउटसोर्स के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होना अपने में ही हास्यपद लगता है। इस तरह के प्रयोगों से नयी शिक्षा नीति कितनी सफल हो पायेगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

भारत की न्याय संहिता में बदलाव के निकलेंगे दूरगामी सकारात्मक परिणाम

गौतम चौधरी

ऐसे तो भारतीय कानून प्रणाली में निरंतर सुधार हो रहा है। समय के साथ बदलाव भी जरूरी है लेकिन हाल में केन्द्र सरकार के द्वारा कानूनी नियमों में जो व्यापक परिवर्तन किया गया है, वह न केवल हमें न्याय दिलाने का आसान मार्ग है, अपितु अब देश की जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध हो पाएगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को न्याय पहुंचाना और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार करना है। हाल ही में भारतीय दंड व साक्ष्य संहिताओं में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव लाने के साथ-साथ न्यायिक प्रणाली के दृष्टिकोण को भी समायोजित किया है। बीते एक जुलाई से बदले गये सारे कानून प्रभावी हो गये हैं। अब उन्हीं कानून के द्वारा हमें न्याय दिलाया जाएगा। या ऐसा कहें कि हम उन्हीं कानून के द्वारा न्यायालय में अपने लिये न्याय मांग सकते हैं। इसलिये इन कानूनों को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही इसकी सकारात्मकता पर भी गौर करने की किया जाना चाहिए।

इस बदलाव का सबसे अहम पक्ष यह है कि इसमें पुलिस की जवाबदेही बढ़ा दी गयी है। मसलन, अब सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है उसे सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जायेगा उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी कर दिया गया है। 20 से अधिक धाराओं में पुलिस की जवाबदेही अनिवार्य होगी। इस बदले गये कानून में पहली बार प्राथमिक अनुसंधान का प्रावधान रखा गया है। बदले गए कानून में राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह की बात कही गयी है लेकिन यदि कोई भारत की संप्रभुता व अखंडता के खिलाफ काम करता है तो उसकी सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कर दी गयी है। इस कानून में अंग्रेजों के काल की गुलामी वाली धाराएं हटा दी गयी है। अब विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसमें सूचना का अधिकार भी दिया गया है। नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की गयी है। अब पीडित या पीड़िता को प्राथमिकी की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जांच की रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर करना जरूरी कर दिया गया है। इस कानून में मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। कानून में साफ कहा गया है कि नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि से प्रेरित हत्या या गंभीर चोट को मॉब लिंचिंग के अंतरर्गत रखा गया है और इसके लिए सात वर्ष की सजा का विधान किया गया है। स्थायी विकलांगता पर यह सजा 10 वर्ष की हो जाएगी या फिर उसे आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है।

नए कानून में न्याय के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के अपराध में 3 वर्ष में सजा दिलाने की बात कही गयी है। अब पीड़ितों को तारीख पर तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुल 35 सेक्शनों में टाइमलाइन जोड़ा गया है। यदि कोई इलेक्ट्रोनिक माध्यम से शिकायत दर्ज कराता है तो तीन दिन में प्राथमिकी दर्ज किया जायेगा। यौन अपराध में जांच 7 दिनों के अंदर भेजना होगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना अनिवार्य होगा। आपराधिक मामलों में सुनवाई की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर निर्णय देना जरूरी कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब किसी को दंड नहीं न्याय दिया जाएगा। भारतीय कानून में किये गये कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों ने न्यायिक प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये गये हैं। ये संशोधन न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को तेजी से और सुलभता से व्यवस्थित करने का प्रयास है, बल्कि न्याय पहुंचाने में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता दिखता है। भारतीय दंड संहिता में नये बदलाव का अहम पक्ष बेहद महत्व का है। अब घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अनुपस्थिति में मुकद्दमा चलाया जा सकता है। यह विशेष रूप से बड़े अपराधों के मामलों में न्याय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

नए कानून में बलात्कार पीड़िता के लिए ई-ब्यान, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और चार्जशीट डिजिटल रूप से होंगे। इससे पुलिस की कारवाई तेज़ और पारदर्शी होगी, जिससे अपराधियों को जल्दी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। भारतीय दंड सहिता में अगला बदलाव, अब 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका अनिवार्य होगी। इससे अपराधियों के खिलाफ प्रमाण जुटाने में सहुलियत होगी साथ ही प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी। ये सुधार भारतीय न्यायिक प्रणाली में बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। विशेषज्ञों की मानें तो इससे न केवल त्वरित न्याय मिलेगा अपितु लोगों को न्याय और न्याय दिलाने वाली संस्थाओं पर भी विश्वास बढ़ेगा। इससे लोकतंत्र में मजबूती आयेगी साथ ही कानून का राज स्थापित करने में आसानी होगी।

इस मामले में हम देखते हैं कि भारतीय कानूनी प्रणाली में नए सुधारों के लागू होने से कानूनी प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार आयेगा। ये सुधार न केवल अपराधियों के खिलाफ तेजी से कारवाई करने में मदद करते हैं, बल्कि भारतीय समाज को न्याय प्रणाली में विश्वास भी दिलाते हैं। इन सुधारों का पालन करने से अपराधियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही न्याय प्रदान करने की क्षमता में सुधार हो सकता है। साथ ही नया कानून गुलामी के प्रतीकों पर भी बड़ा प्रहार है। इसलिये बदले गये कानून एवं दंड सहिता के अंशों का सकारात्मक दृष्टि से स्वागत किया जाना चाहिए।

नीति आयोग ने 'सम्पूर्णता अभियान' शुरू किया

शिमला। नीति आयोग ने 'सम्पूर्णता अभियान' शुरू किया। इसमें देश भर के नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। सभी 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले तीन महीने के इस व्यापक अभियान का लक्ष्य सभी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में संकेतकों की शत-प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करना है। अभियान के पहले दिन जम्मू-कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक जिला और ब्लॉक स्तर के लाखों अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सामुदायिक क्षेत्र की हस्तियों के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों, छात्रों और स्थानीय प्रतिनिधियों ब्लॉक प्रमुखों/सरपंचों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।

आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों ने 'सम्पूर्णता संकल्प' के माध्यम से अपने सिद्धांतों को दोहराते हुए 'सम्पूर्णता अभियान' के लक्ष्यों को पूरा करने और पहचाने गए संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के रतलाम और सिंगरौली जैसे स्थानों पर अभियान के प्रमुख संकेतकों पर जोर देते हुए शिविरों का आयोजन भी शामिल था। इसी तरह, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और हरियाणा के नूंह के जिला मुख्यालयों पर धूमधाम और स्थानीय भागीदारी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के कुराबलाकोटा मंडल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का स्थानीय लोगों ने भारी उत्साह के साथ स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बांसगांव ब्लॉक और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड ब्लॉक में सैकड़ों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए क्षेत्रीय भोजन की पौष्टिक किस्मों को प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुई। 'सम्पूर्णता अभियान' का उत्सव मनाते हुए समर्पित सेल्फी बूथों पर तस्वीरें क्लिक करते खुश चेहरे एक आम दृश्य थे। कुछ स्थानों पर सम्पूर्णता अभियान के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और लक्ष्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संपूर्णता यात्राएं आयोजित की गई। स्कूली बच्चे और एनसीसी कैडेट आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम के भामिनी ब्लॉक में ऐसी ही एक सम्पूर्णता यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बधरा ब्लॉक में बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इस अनूठे कार्यक्रम को समर्थन भी दिया। लॉन्च के अन्य पहलुओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी स्टॉल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण आदि शामिल थे।

उत्तर-पूर्वी राज्यों ने भी पूरे जोश के साथ भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के चौखाम ब्लॉक में सम्पूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। नागालैंड में लॉन्च कार्यक्रम-किफिर को विधानसभा सदस्य एमएलए सी किपिली संगतम ने संबोधित किया, जिससे उत्साहपूर्ण शुरुआत हुई। इसी तरह, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के लामका साउथ ब्लॉक ने लॉन्च कार्यक्रम के लिए मधुमेह और उच्च रक्तचाप पर एक नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।

तीन महीने तक चलने वाले 'सम्पूर्णता अभियान' के हिस्से के रूप में, जिला और ब्लॉक के अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, स्वास्थ्य शिविर, आईसीडीएस शिविर, जागरूकता मार्च और रैलियां, प्रदर्शनी, पोस्टर मेकिंग और कविता प्रतियोगिता जैसी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेंगे, जो सभी आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में शत-प्रतिशत संतृप्ति के लिए पहचाने गए 12 विषयों पर आधारित होंगी।

नीति आयोग के अधिकारी और युवा पेशेवर अभियान को प्रभावी ढंग से आयोजित करने और क्रियान्वित करने में स्थानीय शासन का मार्गदर्शन व समर्थन करने के लिए 300 जिलों में व्यक्तिगत रूप से शुभारंभ किए गए कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ सहयोग से न केवल अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को बल मिलेगा, बल्कि दूरदराज के इलाकों में सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद की भावना को भी मजबूती मिलेगी।

सम्पूर्णता अभियान के फोकस क्षेत्र

आकांक्षी ब्लॉक केपीआई

1. पहली तिमाही के भीतर प्रसवपूर्व देखभाल एएनसी के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
2. ब्लॉक में लक्षित आबादी की तुलना में मधुमेह की जांच करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
3. ब्लॉक में लक्षित आबादी की तुलना में उच्च रक्तचाप की जांच करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
4. आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
5. मृदा नमूना संग्रह लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रतिशत
6. ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूह के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह का प्रतिशत

आकांक्षी जिला केपीआई

1. पहली तिमाही के भीतर प्रसवपूर्व देखभाल एएनसी के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
2. आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
3. पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत 9-11 महीने (बीसीजी+डीपीटी3+ओपीवी3+खसरा 1)
4. वितरित किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या
5. माध्यमिक स्तर पर बिजली की सुविधा से लैस स्कूलों का प्रतिशत
6. शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने वाले स्कूलों का प्रतिशत।

हर तीसरा भारतीय फैटी लीवर से प्रभावित

शिमला। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में यॉत और पित्त विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में चयापचय यॉत रोगों को रोकने और इलाज करने के लिए एक वर्चुअल नोड इंडो-फ्रेंच

लिवर एंड मेटाबोलिक डिजीज नेटवर्क आईएनएफएलआईएमईएन का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडो-फ्रेंच नोड, आईएनएफएलआईएमईएन का उद्देश्य एक सामान्य चयापचय यॉत विकार, गैर-मादक वसायुक्त यॉत रोग एनएएफएलडी से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है। यह स्थिति अंततः सिरोसिस और प्राथमिक यॉत कैंसर के रूप में बदल सकती है। यह मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कई अन्य बीमारियों को बढ़ाता है। स्वयं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के रूप में, मैं वसायुक्त यॉत की बारीकियों और मधुमेह और अन्य चयापचय संबंधी विकारों के साथ इसके संबंध को समझता हूं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप दोनों जीवन शैली में बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। आहार और महत्वपूर्ण रूप से चयापचय संबंधी लक्षण जैसे मधुमेह और मोटापा ने इस रोग को बढ़ाया है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि लगभग 3 में से 1 भारतीय को फैटी लीवर है। जबकि पश्चिम में, अधिकांश एनएएफएलडी मोटापे से जुड़ा रोग है। भारतीय उपमहाद्वीप में, एनएएफएलडी लगभग 20 प्रतिशत गैर-मोटापे के रोगियों में भी होता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, भारत और फ्रांस में एल्कोहोलिक यॉत रोग एएलडी की बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि एनएएफएलडी और एएलडी दोनों ही स्टीटोसिस से स्टीटोहेपेटाइटिस, सिरोसिस और प्राथमिक लीवर कैंसर-लीवर में शुरू होने वाला कैंसर-हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एचसीसी के रूप में बढ़ने लगते हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले दशक में भारत की प्रगति पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत न केवल उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा में बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवा में भी विश्व में अग्रणी बन गया है। फैटी लीवर के विभिन्न चरणों का पता लगाने और गंभीर, पूर्ण विकसित बीमारियों में उनकी प्रगति के लिए सरल, कम लागत वाले नैदानिक परीक्षणों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। दृष्टिकोण और एल्गोरिदम को भारतीय संदर्भ के अनुरूप, कम कीमत वाला और ध्यान रखने योग्य होना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सलाह दी कि बायोमार्कर की खोज के लिए एक व्यापक ओमिक्स दृष्टिकोण का उपयोग करके यॉत रोगों की बढ़ोत्तरी, प्रगति और संभावित प्रबंधन को समझने के लिए आईएनएफएलआईएमईएन जैसे एक संयुक्त बहु-विषयक सहयोगी कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है।

नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग पर बल दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का समर्थन करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से सरकार की पहलों और नीतियों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, भारत में एक बड़ी आबादी चयापचय मेटाबॉलिक संबंधी विकारों से प्रभावित है, क्योंकि हमारा फिनोटाइप अलग है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय समस्याओं के लिए भारतीय चिकित्सा समाधानों की ही आवश्यकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अत्याधुनिक विज्ञान के लिए उदारता से धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि वर्चुअली नोड, कम समय में एक वास्तविक नोड बन जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनके विभाग इस नोड की हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने यॉत और पित्त विज्ञान संस्थान आईएलबीएस द्वारा प्रस्तावित इस नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए विभाग और इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च सीईएफआईपीईआरए के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के सचिव प्रो. अभय करंदीकर की भी सराहना की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यॉत और पित्त विज्ञान संस्थान के सचिव डॉ. शिव कुमार सरीन और उनकी टीम और फ्रांसीसी सहयोगियों को बधाई दी। उन्होंने कम लागत और उच्च उत्पादन के माध्यम से चयापचय मेटाबॉलिक संबंधी विकारों के लिए उपचार खोजने का भी निर्देश दिया। इस नोड में 11 फ्रांसीसी और 17 भारतीय डॉक्टर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक बढ़ाया गया

शिमला। स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी विकास में एक नया प्रयोग है। जून 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, मिशन ने कई नवीन विचारों को अमल में लाने का प्रयास किया है, जैसे कि 100 स्मार्ट शहरों के चयन के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा, हितधारकों द्वारा संचालित परियोजना चयन, कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पज व्हीकल्स का गठन, शहरी शासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों का असरदार तरीके से इस्तेमाल, प्रमुख शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा तीसरे पक्ष के प्रभाव का मूल्यांकन आदि।

100 शहरों में से प्रत्येक ने परियोजनाओं का एक विविध सेट विकसित किया है, जिनमें से कई बहुत ही अनोखी हैं और पहली बार लागू की जा रही हैं, जिससे शहरों की क्षमता और अनुभव में सुधार हुआ है और शहर के स्तर पर बड़े परिवर्तनकारी लक्ष्य हासिल हुए हैं। 100 शहरों द्वारा लगभग 1.6 लाख करोड़ की लागत से 8,000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।

03 जुलाई 2024 तक, 100 शहरों ने मिशन के हिस्से के रूप में 1,44,237 करोड़ की राशि की 7,188 परियोजनाएं कुल प्रोजेक्ट का 90 प्रतिशत पूरी कर ली हैं। 19,926 करोड़ की राशि की शेष 830 परियोजनाएं भी पूरा होने के अंतिम चरण में हैं। वित्तीय प्रगति के मामले में, मिशन के पास 100 शहरों के लिए 48,000 करोड़ का भारत सरकार का आवंटित बजट है। आज तक, भारत सरकार ने 100 शहरों को 46,585 करोड़ भारत सरकार के आवंटित बजट का 97 प्रतिशत जारी किए हैं। शहरों को जारी किए गए इन फंडों में से, अब तक 93 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है। मिशन ने 100 में से 74 शहरों को मिशन के तहत भारत सरकार की पूरी वित्तीय सहायता भी जारी कर दी है।

मिशन को कुछ राज्यों/शहरों की सरकार के प्रतिनिधियों से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, ताकि शेष 10 प्रतिशत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ और समय दिया जा सके। शेष चल रही ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं और विभिन्न स्थितियों के कारण विलंबित हो गई हैं। यह लोगों के हित में है कि ये परियोजनाएं पूरी हों और उनके शहरी क्षेत्रों में जीवन को आसान बनाने में योगदान दें। इन अनुरोधों का संज्ञान लेते हुए, भारत सरकार ने इन शेष 10 प्रतिशत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। शहरों को सूचित किया गया है कि यह विस्तार मिशन के तहत पहले से स्वीकृत वित्तीय आवंटन से परे किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना होगा। सभी चल रही परियोजनाओं के अब 31 मार्च 2025 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने मिलेट्स के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशंसापत्र से सम्मानित होने पर कृषि विभाग की सराहना की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष-2023 के दौरान मिलेट्स के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसापत्र से सम्मानित होने के लिए बधाई दी। प्रदेश के कृषि विभाग को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशंसापत्र से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि विभाग ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मिलेट्स के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य को होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ राज्य में बड़े स्तर पर मिलेट्स की पैदावार करने को प्रोत्साहन प्रदान किया।

कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष-2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में नामित किया गया था ताकि मिलेट्स से मिलने वाले पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास इत्यादि लाभों से लोगों को अवगत करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य प्रणाली भूख, कुपोषण, बढ़ती जनसंख्या, सीमित प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों का समाधान मिलेट्स के रूप में हो सकता है जो विविध पोषक तत्वों से भरपूर है और न्यूनतम संसाधनों के साथ विभिन्न प्रतिकूल जलवायु में उगाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इस पहल के महत्व को समझते हुए, हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने राज्य भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया ताकि किसानों में मिलेट्स की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इन गतिविधियों में मिलेट्स आधारित शिविर, मेले, त्योहार और प्रदर्शनियां शामिल थीं, जिनका उद्देश्य किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करना था। उन्होंने कहा कि विभाग ने आवश्यक तकनीकी इनपुट और बाजार से जोड़कर किसानों को बाजार अधिशेष उत्पादन के लिए प्रेरित किया ताकि वे मिलेट्स की खेती को अपनाएं रखें।

उन्होंने कहा कि नवीन पहल के तहत बीज और मिनी किट वितरण, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, फार्म गेट पर मिलेट्स की बिक्री, और मिलेट्स खाद्य उत्सव इत्यादि आयोजित किए गए। मिलेट्स की खेती और उनके उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जानकारीपूर्ण साहित्य और रेसिपी पुस्तिकाएं भी वितरित की गई। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में 1,526 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 983 मीट्रिक टन मिलेट्स का उत्पादन किया गया।

उन्होंने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के मिलेट्स के प्रचार-प्रसार में सार्थक प्रयासों, पौष्टिक अनाजों के पोषक तत्वों और इनके आर्थिक और पारिस्थितिक लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए।

कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने मिलेट्स की खेती के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।कृषि सचिव सी. पॉलरासु और कृषि निदेशक कुमद सिंह ने किसानों से इस प्रयास को निरन्तर जारी रखने और बाजरा, रागी, कोदो मिलेट, कंगनी, रागी, मंडुआ, सांवां पर विशेष ध्यान देते हुए मिलेट्स उत्पादन को बढ़ाने का आग्रह किया।

देहरा के विकास के लिए मिली विधायक निधि कहां लगाई: चंद्र कुमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने पूर्व निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर तीखे सवाल दागे हैं। उन्होंने पूर्व विधायक से पूछा है कि देहरा के विकास के लिए मिली विधायक निधि कहां खर्च की। जनता जानना चाह रही है कि कहीं होटल और रिजॉर्ट के निर्माण में तो नहीं राशि लगा दी। क्योंकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास न होने से अनेक सवाल उठ रहे हैं। चारों तरफ स्थिति बदहाल है, जिसे देखकर जनता भी तरह-तरह के कयास लगा रही है। साढ़े छह साल में छह करोड़ रुपये से अधिक राशि विधायक निधि के रूप में पूर्व निर्दलीय विधायक को मिली है, होशियार सिंह बताएं कि वह राशि कहां खर्च हुई।

कृषि मंत्री ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। विधायक साढ़े छह साल अपने ही काम करवाते रहे, होटल-रिजॉर्ट व अन्य कार्यो को ही सिरे चढ़ाया। जनता के काम व विकास कार्यों में रूचि नहीं ली। लोग आज भी पेयजल को तरस रहे हैं। सड़कों की हालत खस्ता है। बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लो वोल्टेज के कारण बल्व भी नहीं जलते। अनेक गांवों तक सड़क नहीं पहुंची है। गुलेर और नंदपुर को जोड़ने वाले पुल आज भी अधर में क्यों लटका है। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने इन समस्याओं के लिए कितनी बार आवाज उठाई। वह विधायकी से इस्तीफा देकर उसे मंजूर करवाने के लिए विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए, अच्छा होता देहरा की समस्याओं के समाधान के लिए धरना देते। मगर नहीं, क्योंकि उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। वह तो अपना व्यापार व धन संपदा बढाने के लिए राजनीति में हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद देहरा को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का काम किया है। बनखंडी जूलॉजिकल पार्क देहरा विधानसभा क्षेत्र को देश-प्रदेश के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध करेगा। इस जूलॉजिकल पार्क में अंतरराष्ट्रीय स्तर की जंगल सफारी होगी। विदेशों की तरह सफारी में अनेक तरह की सुविधाएं व पर्यटन के साधन उपलब्ध होंगे। देहरा को एसपी जिला बनाकर हमारी सरकार ने साबित कर दिया कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। एसई पीडब्ल्यूडी का कार्यालय हमने देहरा को दिया है। इसके अलावा अनेकों काम हुआ है। बिजली, पानी, सड़कों व पुलों की समस्या जल्द हल हो जाएगी।

चंद्र कुमार ने कहा कि निर्दलीय विधायक ने 14 महीने में लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया और राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे रहे। जब उन्हें जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा था तो फिर 14 महीने बाद विधायकी छोड़कर दोबारा विधायक का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं।

गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के विकास, फसल विविधीकरण पर दिया ज़ोर

शिमला। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की 26वीं अनुसंधान परिषद की बैठक कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल की अध्यक्षता

में आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर सुशील कुमार सिंगला, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के परियोजना निदेशक सुदेश कुमार मोखटा, वन संरक्षक सोलन बसु कौशल सहित प्रगतिशील किसानों और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान ने पिछले वर्ष की गई अनुसंधान गतिविधियों का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने सेब में बड म्यूटेंट की पहचान करने और नई किस्मों को विकसित करने के लिए चल रहे परीक्षणों में विश्वविद्यालय की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती में अपने अनुसंधान के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त किया है और इस विधि का एक अग्रणी अनुसंधान केंद्र बनकर उभरा है। डॉ. चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय ने क्लोनल रूटस्टॉक्स के बड़े पैमाने पर गुणन के लिए मॉड्यूल विकसित किए हैं। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट, जूजूबे बेर, कॉफी, ब्लूबेरी और एवोकैडो जैसे नए फलों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की पहल को साझा किया है, जिसके लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं।

प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने वन और बागवानी विभागों की प्राथमिकता वाली प्रजातियों को ध्यान में रखकर बागवानी और वानिकी पौधों के लिए विशिष्ट रोपण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे मॉडल बनाने के महत्व पर जोर दिया जो कम पानी वाली परिस्थितियों में अच्छा काम कर सकें। उन्होंने वैज्ञानिकों से छोटे मॉडल विकसित करने का आग्रह किया जिन्हें किसानों के खेतों में आसानी से दोहराया जा सके। प्रोफेसर चंदेल ने जलवायु-लचीली कृषि के महत्व और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और प्राकृतिक खेती की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कम उपयोग वाले और कम प्रसिद्ध देसी फलों को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के बारे में बताया।

सुशील कुमार सिंगला ने सदस्यों को संबोधित करते हुए अनुसंधान परियोजनाओं के वित्तपोषण में निजी क्षेत्र को शामिल करने के महत्व और किसी भी परियोजना की सफलता में सामुदायिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सुदेश कुमार मोखटा ने राज्य के विकास को बागवानी की प्रगति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जहां टेम्परेट बागवानी काफी आगे बढ़ चुकी है वहीं सब ट्रोपिकल बागवानी को आगे बढ़ाने से राज्य भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बागवानी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में राज्य के समृद्ध ज्ञान आधार का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए हस्तक्षेप, जल संरक्षण के लिए स्प्रिंगशेड पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन दृष्टिकोण और जंगल की आग के प्रबंधन के लिए सिल्वीकल्चर हस्तक्षेप पर भी चर्चा हुई। चर्चाओं में विभिन्न वन पौधों की नर्सरी तैयार करने की प्रथाओं का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस शामिल रहा। किसानों ने बढ़ते सेब मोनोकल्चर के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और विविधीकरण विकल्पों पर किसानों को शिक्षित करने का आहवान किया। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, स्प्रे शेडयूल कार्यान्वयन, कोल्ड चेन नेटवर्क का शोधन, जोखिम शमन जैसे विषय भी बैठक का हिस्सा रहे।

बैठक के दौरान, छः प्रकाशन का विमोचन किया गया, जिनमें उच्च घनत्व वाले सेब बागानों और प्रबंधित परागण पर पैकेज शामिल था। बैठक में प्रगतिशील किसान उमेश सूद, शैलेन्द्र शर्मा, सुभाष शार्दू, बांके बिहारी, विनय नेगी और मोहिंदर कुमार सहित जी. आई.जेड सलाहकार अजीत भोर, कृषि विवि पालमपुर से डॉ. एमसी राणा, विश्वविद्यालय के वैधानिक अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

सरकार सड़को के निर्माण,रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार सड़को के निर्माण, इनके रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बरसात के कारण सड़को में पानी की निकासी बेहतर ढंग से हो इसके लिए विभाग को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नालागढ़ का यह क्षेत्र ओद्योगिक विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही विकास की राजनीति की है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव थोप कर प्रदेश के विकास को विराम लगाया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में तीन पूर्व निर्दलीय विधायको ने भी नालागढ़, देहरा व हमीरपुर क्षेत्र के लोगों के विश्वास को तोड़ा है जिन्होंने उन्हें पांच साल के लिये अपने वोट से विधानसभा में चुन कर भेजा था। उन्होंने कहा कि यह तीनों निर्दलीय पूर्व विधायक अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे है, इससे साफ है कि इन निर्दलीयों ने अपना ईमान बेच कर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह मजबूत और स्थिर है जो अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

विक्रमादित्य सिंह ने लोगों से हरदीप सिंह बाबा को भारी मतों से विजयी बनाने का आहवान करते हुए कहा कि बाबा के विधायक बनने से इस क्षेत्र में विकास की गति को चार चांद लगेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा कांग्रेस के एक कर्मठ नेता है जो हमेशा लोगों व श्रमिकों के कल्याण के प्रति समर्पित रहते है।

शिलारु फल मंडी का निरीक्षण के बाद होगा उद्घाटन

शिमला/शैल। कुलदीप राठौर ने कहा कि ठियोग के शिलारू फल मंडी बनकर तैयार है। एक दो दिनों में उनका यहां जाने का कार्यक्रम है। पहले मंडी का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इसका उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश इसी सीजन में इस मंडी को तैयार कर समर्पित करने की रहेगी।

कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब सीजन के दौरान सभी सड़कें खुली रहेगी। इसके लिए हाल ही में उन्होंने राज्य लोक निर्माण विभाग व नेशनल हाइवे अर्थीटी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। राठौर ने कहा कि जो सड़के लोक निर्माण के अधीन नहीं है उन्हें भी सेब सीजन के दौरान मेंटेन रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी अन्य मद से इसके लिए पैसा दिया जाएगा।

उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद हिमाचल की राजनीति में भूचाल तय:जयराम

शिमला/शैल। विधानसभा उपचुनाव में हमीरपुर के भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने डेढ़ सालों में झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। सरकार सिर्फ़ झूठ पर झूठ बोले जा रही है। डेढ़ साल से सरकार सिर्फ़ आश्वासन दिए जा रही है। इस सरकार के पास बताने के लिए एक काम नहीं हैं। जिसके दम पर वोट माँग सके। नालागढ़ में जाएंगे तो कहेंगे देहरा में मिल गई सम्मान निधि, देहरा जाएँगे तो कहेंगे हमीरपुर में मिल गई सम्मान निधि। आज तो देहरा के लोगों ने मंच पर मुख्यमंत्री के सामने ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि उन्हें कोई सम्मान निधि नहीं मिली है। इस तरह के झूठ से सरकार कितने दिन बची रहेगी। अब बहुत हो गया प्रदेश के लोग सरकार के झूठ का काम तमाम करने के लिए बैठे हैं। इस उपचुनाव में जनता ही सुक्खू सरकार का फॉर्म भरने वाली है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि चारों लोक सभा सीटों की तरह इस बार के उपचुनाव भी भाजपा जीतेगी। भाजपा के प्रत्याशियों के जीतते ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल आना तय है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। प्रदेश में सरकार की तानाशाही का दौर बीतने वाला है। अब प्रदेश के लोग कांग्रेस सरकार की जोर-ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ आवाज उठा रहे हैं, एक जुट हो रहे हैं। इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिल रहा समर्थन इस बात की गवाही दे रहा है कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में मंत्री तो मंत्री मुख्यमंत्रे भी अपना हलका नहीं बचा पाये। इस बार भी यही हाल होगा, सभा भाजपा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर हैं और क़ानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार के संरक्षण में माफिया पैर पसारे है। आये दिन घोटाले सामने आ रहे हैं। घोटालों की फ़ेहरिस्त बढ़ने वाली है। प्रदेश का सारा तंत्र भाजपा के नेताओं और प्रत्याशियों के खिलाफ लगा दिया गया है। सरकार व्यवस्था सुधारने के बजाये भाजपा के नेताओं के घर गिराने, डंगे गिराने, रास्ता बंद करने, बिज़नेस बंद करने, गाड़ियां बंद करने, झूठे मुक़द्दमों में फ़सानें में व्यस्त है। अब तानाशाही का यह दौर बस ख़त्म होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौक़े पर उनके साथ विधायक रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, दिलीप ठाकुर, इन्द्र दत्त लखनपाल और हमीरपुर कि पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर समेत स्थानीय पदाधिकारी और हज़ारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

माइनिंग पॉलिसी में बदलाव करने की क्या आवश्यकता थी:सिकंदर

शिमला/शैल। भाजपा राज्य सभा सांसद एवं नालागढ़ विधानसभा उप चुनाव के संयोजक प्रदेश महामंत्री डॉ सिकंदर कुमार ने कहा कि अब तो कांग्रेस के विधायक स्वयं मान चुके है की कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से हो रहा है। हर विभाग से पैसे का लेन देन हो रहा है। इस प्रमाण में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं हिमाचाल के विधायक ने अपनी ही सरकार को घेर दिया है।

जिला शिमला के उपमंडल ठियोग में 17 करोड़ रुपये की लागत से बने सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य जांच की जद में आ गया है। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामियां सामने आयी। अस्पताल भवन के अंदर सीलन पायी गयी और टाइलें भी उखड़ना शुरू हो गई हैं। निरीक्षण के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता समेत अन्य अधिकारी भी साथ थे। विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने इस मामले की जांच के आदेश एसडीएम ठियोग को दिये हैं। उन्हें एक महीने के भीतर इस मामले की पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस मामले में आगामी कारवाई करेगी। कांग्रेस विधायक ने खुद माना है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ कारवाई होगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा बार बार माइनिंग पोलिसी को लेकर सवाल उठा रही है, पर सरकार मौन है और इस प्रकार के आरोप जो कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी पर लगाये है इस बात को पुष्टी करता है की मुख्यमंत्री हिमाचल में हो रहे भ्रष्टाचार के कुलपति है। जब कुलपति ऐसा हो तो कुल तो भ्रष्ट होगा ही।

मुख्यमंत्री से हम पूछते है कि माइनिंग पॉलिसी को बदलने की क्या नौबत आ गई इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा।

विकास कार्यों पर तालाबंदी कांग्रेस की निशानी:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव में नालागढ़ में जनसंपर्क व जनसभा के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर को भारी मतों से विजयी बनाने व नालागढ़ में कमल खिलाने का आहवाहन किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश में जब-जब कांग्रेस सत्ता में आती है। विकास कार्य ठप्प हो जाता है, क़ब्ज़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। नालागढ़ में केएल ठाकुर ने भाजपा के डबल इंजन की सरकार में लगभग 550 करोड़ रुपये के विकास कार्यो यहां लाने का काम किया मगर प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी दुर्भावना से ग्रसित होकर विकास कार्यो पर तालाबंदी करने का काम किया है। कांग्रेस ने मात्र 1.5 साल में 25000 करोड़ का कर्ज लेकर प्रदेश पर कर्ज का बोझ 95000 करोड़ पहुंचा दिया। कांग्रेस ने प्रदेश को दिया तो कुछ नहीं लेकिन यहां चल रहे स्वास्थ्य संस्थान, शिक्षा केंद्र, सरकारी स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली वर्दीयां हों या मज़दूरों को मिलने वाली सुविधाएं हों सब बंद करने का काम किया। कांग्रेस बताये आखिर जनता का क़सूर क्या है। एक तरफ़ वो कहते हैं कि हमने हिंदुओं को हराकर कांग्रेस की सरकार बनाई दूसरी तरफ़ वो मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी व सड़क के लिए भी प्रदेश की जनता को तरसा रहे हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल की सरकार अपने ही उद्योगों को चौपट करने में लगी है जबकि मैंने हमारे ट्रक यूनियन के अनुरोध पर मध्यप्रदेश की सरकार से बात करके एंट्री टैक्स बंद करा कर प्रति ट्रक 2500 रुपये का फ़ायदा कराने का काम किया है। कांग्रेस बताये कि उसने प्रदेश के हित में पिछले 18 महीने में क्या काम किया है। झूठी गारटियाँ देकर सिर्फ़ जनता को ठगने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा अगर हिमाचल के नालागढ़ व इसके साथ लगते इलाक़ों में लगे उद्योगों में 7 लाख लोग कार्यरत हैं तो वह श्रेय अटल बिहारी वाजपेई की सरकार और प्रेम कुमार धूमल की सरकार में संभव हुआ था। यह औद्योगिक पैकेज अटल जी और धूमल जी की सरकार के समय 2002 में मिला था, मगर उसके बाद की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी अड़ंगा लगाया। कांग्रेस भाजपा के हर विकास कार्यो को रोकने का भरसक प्रयास करती रही हैं। नालागढ़ में भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर जी ने कभी सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखी। के एल ठाकुर जी ने भाजपा की सरकार के समय नालागढ़ में अभूतपूर्व विकास कार्यो को धरातल पर उतारने का काम किया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने लोकसभा चुनाव में हर ताकत का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी नालागढ़ के लोगों ने हमें यहां से 15000 से ज्यादा वोटों की लीड दिलाई। मोदी सरकार ने तीन बार पेट्रोल और डीजल का दाम कम किया लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 महीनों में हीं दो बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा कर जनता पर महंगाई का बोझ डाला है

प्रदेश में सुक्खू सरकार का गणित बिगड़ चुका:रविंद्र रवि

शिमला/शैल। भाजपा के कद्दावर नेता, पांच बार के विधायक रहे व पूर्व में मंत्री ठाकुर रविंद्र सिंह रवि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि वे उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशियों की फिक्र करने की बजाये अपनी सरकार की फिक्र करें जो जल्द गिरने वाली है। उन्होंने का कि कांग्रेस सरकार का गणित मुख्यमंत्री सुक्खू की वजह से बिगड़ चुका है। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सुक्खू सरकार का गणित उल्टा ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि देहरा विधान सभा क्षेत्र में सुक्खू व उनके विधायक घटिया भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। सुक्खू ने पत्नी की जीत को लेकर देहरा में जो आतंक का माहौल बनाया हुआ है उसे जनता देख व भुगत रही है। जनता इसका बदला 10 जुलाई को लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि देहरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह एक कद्दावर नेता के रुप में उभर कर जनता के सामने आये हैं। देहरा की जनता ने दो बार उन्हें भारी बहुमतों से अपना विधायक चुना है तथा देहरा उपचुनाव में होशियार सिंह की जीत फिर से तय है। देहरा की जनता सुक्खू सरकार के लालच में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सुक्खू प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनके उपर लगातार खतरा मंडराया हुआ है। उन्होनें कहा कि सुक्खू अपनी जनसभाओं में अपमानजनक भाषण दे रहे हैं। भाजपा नेता रवि ने कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश के विकास को पूरी तरह से ठप कर दिया है। सुक्खू अपनी मित्र मंडली को लाभ पहुंचाने में लगे हुए हैं। सुक्खू झूठ के ठेकेदार के रुप में उभरकर सामने आये हैं। वे लोगों को ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। उन्होनें कहा कि होशियार सिंह देहरा की जनता के दिलों में राज करते हैं। देहरा की जनता जानती है होशियार सिंह ने देहरा के क्या किया तथा 15 माह में सुक्खू सरकार ने किया किया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद न तो सुक्खू और न ही उनकी पत्नी कभी दजर आएंगी। इस लिए जनता बोल उठी है देहरा होशियार सिंह ही तेरा।

प्रदेश में कबाड़ माफिया, खनन एम, चिट्टा माफिया हावी:बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने नालागढ़ में युवक-युवतियों से मिल कर उन्हें सम्बोधित किया। उन्होंने कहा की युवा वर्ग हमारे देश-प्रदेश का भविष्य है

और वे जानते हैं कि उन्हें अपना वोट विकास, गरीब कल्याण करने वाली भाजपा सरकार के पक्ष में करना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि युवा वर्ग प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जोकि पति-पत्नी और मित्रों की सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, बेरोजगारों को ठगने वाली सरकार है, को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने के लिए भाजपा प्रत्याशी के एल ठाकुर जी को विजयी बनाएगा।

उन्होंने कहा की हिमाचल प्रदेश माफिया की गिरफ्त में है, जनता त्रस्त है और सरकार अपने घर में मस्त है। आजकल साकार का घर देहरा बन रखा है जहां उनका घर है ही नही, सवाल यह उठता है की मुख्यमंत्री कहां से है? शिमला, हमीरपुर या देहरा। इस का चयन तो असंभव हो गया है।

बिंदल ने कहा कि बीबीएम में गोलीकांड सुर्खियों में है, सरकार में हिमाचल में माफिया को संरक्षण दे रखा है। उल्टा माफिया ही सरकार चला रही है। कबाड़ माफिया, खनन माफिया हावी है। हिमाचल में नशे के सौदागर सक्रिय है यह किसकी देन है, यह कांग्रेस की मित्रमंडली , मित्रों के टीले की देन है।

हिमाचल प्रदेश में गोलियां चलना आम हो गया है, जनता असुरक्षित महसूस कर रही है।

उन्होंने कहा की छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंस गया है इसके लिए और कोई नही अपितु मुख्यमंत्री और उनका मित्रों का टोला जिम्मेदार है, एक दशक से कैग यानी कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिस डेब्ट ट्रैप की तरफ इशारा कर रहा था, वो अब हकीकत बन चुका है। हिमाचल को मुख्यमंत्री जल्द 1 लाख करोड़ लोन फिगर तक पहुंचा देंगे।

देहरा व नालागढ़ की कुल 217 पोलिंग पार्टियां रवाना

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने वाले उप-चुनावों के लिए 10 जुलाई, 2024 को होने वाले मतदान के लिए स्थापित कुल 315 मतदान केन्द्रों में से 217 के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि कांगड़ा जिला के देहरा में स्थापित 100 मतदान केन्द्रों के लिए 98 तथा सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थापित 121 मतदान केन्द्रों के लिये आज 119 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं।

उन्होंने बताया कि देहरा व नालागढ़ की दो-दो महिला पोलिंग पार्टियां और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी 94 पोलिंग पार्टियों को 9 जुलाई, 2024 को रवाना किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या वित्त विभाग भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के खिलाफ जा सकता है

➤ विद्युत बोर्ड के टैण्डर प्रकरण से उठा सवाल

➤ क्या अलग–अलग निकायों के लिए अलग–अलग नियम हैं जीआईसी के ऑफलाईन टैण्डर से उठा सवाल

शिमला/शैल। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आबंटित एक टैण्डर को लेकर सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा हमला बोला है। सुधीर शर्मा के मुताबिक 175 करोड़ के टैण्डर को 245 करोड़ में और वह भी सिंगल बिड के आधार पर ही आबंटित करके घपला किया गया है। सुधीर शर्मा ने अपने आरोप में यह भी कहा है कि इस आबंटन पर विशेष सचिव वित्त ने भी आपत्ति उठाकर अपनी असहमति दर्ज कराई है। यह आरोप सामने आने के बाद बोर्ड प्रबन्धन ने इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुये आरोपों को पूरी तरह गलत और अधूरा करार दिया है। प्रबन्धन के स्पष्टीकरण के बाद सुधीर शर्मा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है। लेकिन प्रबन्धन के इस स्पष्टीकरण से सरकार के वित्त विभाग की समझ और नीति पर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं।

सारे सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में वित्त विभाग की पदेन सदस्यता रहती है ताकि कोई भी प्रबन्धन वित्तीय नियमों की अवहेलना न कर सके और उसे सरकार के नियमों की जानकारी रहे। विद्युत बोर्ड के जिस टैण्डर आबंटन पर विशेष सचिव वित्त ने चौदह आपत्तियां उठाई थी उनका निदेशक मण्डल में विस्तृत जवाब दिया गया और उसके बाद निदेशक मण्डल ने सात–एक के बहुमत से उन आपत्तियों को खारिज करके टैण्डर का अनुमोदन कर दिया। जिस परियोजना के लिये यह टैण्डर जारी किया गया है उसका वित्त पोषण आई.बी.आर.डी. की ओर से किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 29 अक्तूबर 2021 को सिंगल निविदा के विषय में विस्तृत नियमावली अधिसूचित है। इसके मुताबिक **Rejection of single Bid :** It has become a practice among some procuring entries to routinely assume that open tenders which result in single bids are not acceptable and to go for re-tender as a safe course of action. This is not correct. Re-bidding has costs: firstly the actual cost of the re-tendring, secondly the delay in execution of the work with consequent delay in the attainment of the purpose for which procurement is being done , and thirdly the possibility that the re-bid may result in a higher bid.

That tender was floated on terms and condition of Standard Bid Documents (SBD) which was duly approved by the WTD in 92nd meeting held on 29-09-2021 vide agenda item number 92.06 which was later also approved by the ACS(Power)-cum- chairman HPSEBL on 15-03-2022. The CE (MM) being nodal officer for the same has issued guidelines and amendments form time to time in this SBD. Technical specification of items of tender are as per HPSEBL's requirements. No bidder has approached for changing any specifications/ terms and conditions/ revisiting technical specifications of contract. Hence objection is not sustainable.

बोर्ड प्रबन्धन के स्पष्टीकरण के मुताबिक भारत सरकार द्वारा तय इस प्रक्रिया की पूरी अनुपालना की गयी है। प्रबन्धन के मुताबिक इसमें तीन बार समय अवधि बढ़ाई गयी थी लेकिन कोई भी नया बोलीदाता नहीं आया। इसलिये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रिया नियमावली के अनुपालना करते हुये यह टैण्डर आवंटित किया गया है।

प्रबन्धन के मुताबिक प्राइस ईंडैक्स के अनुसार इसका मूल्य केवल 65 करोड़ ही बढ़ा है। इस निविदा में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की दरों पर इसकी कीमत वर्ष 2023–24 के लिये 224 करोड़ बनती है जबकि वर्तमान वित्त वर्ष 2024–25 में यह निविदा 240 करोड़ की स्वीकृत हुई है। बोर्ड प्रबन्धन ने सवाल उठाया है कि स्मार्ट मीटरिंग निविदा में मूल्य दो गुणा हो गया क्योंकि उसे पिछली सरकार में अनावश्यक कारणों से रद्द किया गया। लेकिन इस पर वित्त विभाग ने कभी कोई आपत्ति नहीं उठायी। यही नहीं सरकार ने पांच लाख से अधिक की खरीद के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश जारी कर रखे हैं। इसके लिये एक पोर्टल भी बनाया गया है। इन निर्देशों की अनुपपलना किया जाना अनिवार्य है। लेकिन पिछले दिनों 13 मार्च को जीआईसी द्वारा शिक्षा विभाग के लिये खरीदारी करने के लिए करोड़ों की निविदा ऑफलाईन आमंत्रित कर ली। लेकिन इस पर भी प्रदेश का वित्त विभाग खामोश रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि वित्त विभाग अलग–अलग उपक्रमों के लिये अलग–अलग नियमों पर अमल कर रहा है।

इस समय जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसमें अधिकारियों का ऐसा आचरण आने वाले समय में सरकार के लिये कठिनाइयां पैदा कर सकता है। क्योंकि इस समय प्रदेश की राजनीति आरोपों और प्रत्यारोपों के दौर से गुजर रही है। बहुत सारे मामलों में अधूरी जानकारियां बाहर आने से अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना बन जाती है। जैसे विद्युत बोर्ड के मामले में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया नियमावलि को पूरी तरह समझे बिना एक घपले की संज्ञा दे दी गयी।

क्या यह छापेमारी

पृष्ठ 1 का शेष

नादौन रियासत में ऐसी जमीनों के दर्जनों प्रभावशाली लोग निकल आयेंगे। जबकि विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच हो ही नहीं सकती। ऐसी खरीद बेच अपराध की श्रेणी में आती है। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2011 में पारित अपने फैसले में देश के सभी मुख्य सचिवों को विलेज कामन लैण्ड को प्रोटैक्ट और रीस्टोर करने के निर्देश देते हुये समय–समय पर इसका जानकारी शीर्ष अदालत को देने को कह रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों के बाद ऐसे मामलों की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। संभव है जिस होटल की जांच अब की गयी है उसकी जांच में जमीन से जुड़ा यह पक्ष भी सामने आये और इसके दायरे में और भी कई लोग आ जायें। क्योंकि इस तरह की खरीद– बेच सीधे सरकारी संपत्ति पर डाका डालने के दायरे में आ जाता है। इसमें प्रशासन की भूमिका भी जांच के बारे में आ सकती है।

जिस राजनीतिक परिदृश्य में प्रदेश में केंद्रीय जांच एजैन्सियों के दखल की स्थिति बनी है उसके परिणाम निश्चित रूप से गंभीर होंगे। क्योंकि इसमें शिकायतों का सिलसिला लंबा होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार से जमीन लीज पर लेकर उस पर फ्लैट बनाकर बेचने को लेकर कई लोगों के नाम चर्चा में आ गये। राजा नादौन की विलेज कामन लैण्ड बनी जमीन की खरीद–बेच में संलिप्त ऐसे लोग भी मिल जायेंगे जिन्होंने ऐसी जमीनें लैण्ड सीलिंग की सीमा से भी अधिक खरीद रखी है उसमें नादौन और हमीरपुर के प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिवों तक आंच आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। केंद्र की इन जांच एजैन्सियों के दखल का प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा यह तय है।

उपचुनाव में सरकार

पृष्ठ 1 का शेष

अधिकारी दिल्ली जाने के लिये प्रयासरत हो गये हैं। जब शीर्ष प्रशासन में इस तरह की स्थितियां जन चर्चा में आ जाती है तो माना जाता है कि बड़े बाबू सरकार को लेकर बहुत ज्यादा अश्वस्त नहीं रह गये हैं। यह संदेश जा चुका है कि सरकार कर्ज के सहारे चल रही है। जब कर्ज का जुगाड़ होने पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा उसी के साथ सरकार का भविष्य प्रश्नित हो जायेगा। विपक्ष हर रोज सरकार गिरने की आशंकाएं व्यक्त कर रहा है। विपक्ष के ब्यानों से एक मनोवैज्ञानिक वातावरण सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। सीपीएस के फैसले और नौ भाजपा विधायकों के संभावित निष्कासन को लेकर जिस हद तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें खींच चुकी हैं वह जगजाहिर है। विश्लेषकों की नजर में इस तरह का वातावरण कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहता है। इस परिदृश्य में चुनावों में सरकार के नुकसान की संभावना झलकने लगी हैं।